भारत में रोजगार से जुड़ी चुनौतियां

आने वाले समय में ऐसे लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना एक चुनौती होगी जो रोजगार में तो लगे हैं, लेकिन अधिक आय की लालसा रखते हैं।

अमिताभ कांत , (लेखक नीति आयोग के सीईओ है।)

यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) पीएलएफएस के नतीजों की पिछले रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) से तुलना नहीं की जा सकती। पीएलएफएस का इस्तेमाल 2017-18 के आधार से बदलावों को मापने में किया जाना चाहिए। हम पहले भी यह देख चुके हैं। भारत में सर्वेक्षण करना हमेशा पेचीदा रहा है और सर्वेक्षण पद्धति में छोटे से बदलाव से अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं। पीएलएफएस में श्रम बल की भागीदारी की दर में गिरावट को भी उजागर किया गया है। अगर यह सही भी है तो इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी वजह स्कूलों में उपस्थिति में बढ़ोतरी या उच्च शिक्षा जैसे कारक हो सकते हैं।

समस्या सर्वेक्षण की पद्धति में है। नमूने का आकार बहुत छोटा था, जबकि तकनीक की मदद से ज्यादा परिवारों से प्रतिक्रिया हासिल की जा सकती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए परिवारों की संख्या महज 55,000 थी। इसे देश में 16 करोड़ परिवारों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस तरह नमूने का प्रतिशत 0.03 फीसदी यानी हर 10,000 पर करीब तीन परिवार। परिवारों के चयन में भी 75 फीसदी भारांश उन परिवारों को दिया गया, जिनमें 15 साल से अधिक उम्र के 10वीं पास लोगों की संख्या अधिक थी। वर्तमान स्थिति में 15 साल की उम्र के बाद भी शिक्षा को जारी रखने की संभावना होती है। 15 से 18 साल की उम्र के ज्यादातर लोग शिक्षा ग्रहण करना जारी रखते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं, वे इस तरीके से जबाव देंगे कि वे रोजगार ढूंढ रहे हैं। नमूने का आकार इतना छोटा है कि आंकड़ों की संवेदनशीलता बहुत अधिक होगी। शहरी परिवारों में एक परिवार के प्रत्येक क्षेत्र में गलत जवाब देने पर श्रम बल की भागीदारी दर संख्या 25 फीसदी के दायरे में दिखेगी। इनकी तात्कालिक आंकड़ों से पुष्टि करने का कोई स्रोत नहीं है। सर्वेक्षण में जिन सर्वेयरों की सेवाएं ली गईं, वे बाहरी एजेंसी के थे। यह जरूरी नहीं कि वे लोगों से

बातचीत करने के लिए सही व्यक्ति हों। हालांकि इन सर्वेयरों को डेटा रिकॉर्डिंग के लिए एक टैबलेट मुहैया कराया गया, लेकिन उन्हें सिम और डेटा कनेक्टिविटी नहीं दी गई। यहां तक कि जगहों की भी तस्वीरें नहीं ली गईं। मैं इस बात से अचंभित हूं कि आज की दुनिया में भी तात्कालिक डेटा और तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में रोजगार सृजन की स्थिति क्या है? सामाजिक सुरक्षा लाभों में योगदान देने वाले लोगों के बारे में अब हमारे पास वृहद आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आंकड़े हमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और राष्ट्रीय पेंशन फंड (एनपीएस) के माध्यम से प्राप्त होते हैं। सितंबर 2017 से नवंबर 2018 तक ईपीएफओ के साथ 73,50,786 नौकरीशुदा लोग जुड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो हरेक महीने कुल 490,000 लोग इससे जुड़े हैं। ईएसआईसी भी लगभग यही कहानी बयां करता है। सितंबर, 2017 से नवंबर 2018 के बीच औसतन लगभग 10 से 11 लाख लोग हरेक महीने ईएसआईसी के साथ जुड़ते चले गए। थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि इनमें 50 प्रतिशत लोग ईपीएफओ से भी जुड़े हैं तो भी हरेक महीने 1 लाख और सालाना 12 लाख लोग औपचारिक रोजगार के दायरे में आए। एनपीएस का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सरकार केंद्र एवं राज्य सरकारों में 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हो रही हैं।

देश में परिवहन क्षेत्र भी रोजगार के आंकड़े की झलक पेश कर रहा है। इसके लिए व्यावसायिक वाहनों की बिक्री पर विचार करें। भारत में वित्त वर्ष 2018 में 750,000 वाहनों की बिक्री हुई। इनमें अगर 25 प्रतिशत नए वाहन पुराने वाहनों की जगह खरीदे गए हैं तो भी आंकड़ा 560,000 के करीब रहता है, जो किसी दृष्टिकोण से कम नहीं है। अगर हरेक वाहन दो लोगों को रोजगार दे रहा है तो इस दर से इस क्षेत्र में सालाना 11 लाख नौकरियां जोड़ी जा रही हैं। इनमें अगर कारों की बिक्री भी शामिल कर लें तो केवल इस क्षेत्र में सालाना 30 लाख नौकरियां सृजित हो रही हैं। भारत में स्वरोजगार भी रोजगार सृजन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। पेशेवर सेवा प्रदाताओं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और डॉक्टर के माध्यमों से भी रोजगार सृजन होता है। इन पेशेवरों के कामकाज पर नजर और इनका नियमन करने वाली संस्थाओं के आंकड़ों से यह बात जाहिर हो जाती है।

आयकर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे नए स्वरोजगार का संकेत दे रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार समीक्षा वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच कर दाखिल करने वाले सालाना 150,000 नए पेशेवर जुड़े। इससे यह भी पता चलता है कि इनमें ज्यादातर करदाता सहायता के लिए कर्मचारी रखते हैं, जिनकी संख्या 20 से कम होती है। कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक होने पर सामाजिक सुरक्षा पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाता है। अगर प्रत्येक पेशेवर पांच लोगों की भी सेवाएं लेता है तो यह आंक ड़ा बढ़कर सालाना 750,000 हो जाता है। मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ ऋण जारी हो चुके हैं। इन ऋणों का कुल मूल्य

करीब 7 लाख करोड़ रुपये होता है। पहली बार ऋण लेने वाले 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने कारोबारी उद्यम शुरू किए हैं। छोटे उद्यमियों को इतनी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं।

मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'इंडियाज लेबर मार्केट-अ न्यू एम्फेसिस ऑन गेनफुल इम्प्लायीमेंट' में कहा गया है कि सरकार की तरफ से व्यय बढऩे और स्वतंत्र रोजगार और उद्यमशीलता का विकास होने से 2014-17 के दौरान 2 से 2.6 करोड़ लोगों के लिए रोजगार बढ़े हैं। पर्यटन मंत्रालय के एक विश्लेषण के अनुसार पिछले चार वर्षों में अकेले पर्यटन क्षेत्र ने 1.46 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। हालांकि ऊपर वर्णित आंकड़े रोजगार सृजन का पूर्ण ब्योरा नहीं देते हैं, लेकिन ये देश में तेजी से हो रहे रोजगार सृजन का पुख्ता प्रमाण हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ रोजगार कम होने जैसी धारणा नकारने के लिए ये आंकड़े पर्याप्त हैं।

क्या इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारत में रोजगार से जुड़ी चुनौतियां नहीं हैं? ऐसा कहना भी सच्चाई से भागना होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की मुख्य चुनौती उन लोगों की अपेक्षाएं पर खरा उतरने की है, जो रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन अधिक आय की लालसा रखते हैं। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के मौजूदा कर्मचारियों और जो लोग कृषि क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए अधिक आय देने वाली नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति तैयार करने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत होगी, जो देश में उत्पादकता बढ़ाती हैं। जहां तक पीएलएफएस की बात है तो मेरा मानना है किइस परियोजना से मिले अनुभव को आधार पर बनाकरतकनीक और वास्तविक समय के आंकड़े के इस्तेमाल से और नमूने का आकार बढ़ाकर सर्वेक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। केवल मोटे अनुमानों से मदद नहीं मिलती है। अगर आयोग के सदस्य के तौर पर एक प्रति मुझे मिली होती या मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए संपूर्ण आयोग की बैठक हुई होती तो ये मुद्दे मैंने उठाए होते।

ब्याज का लचीलापन

संपादकीय(Dainik Jagran)

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अर्से बाद अपनी मुख्य ब्याज दर रेपो रेट घटाई है। सारे भारतीय बैंक इसी दर पर रिजर्व बैंक से पैसे उठाते हैं। रेपो रेट में चौथाई फीसदी यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिससे यह 6.50 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी हो गई है। आरबीआई ने अपनी ब्याज दर में कमी

पिछली बार अगस्त 2017 में की थी। उसके नए गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल की यह पहली मौद्रिक नीति है। पूर्व वित्त सचिव दास को बीते दिसंबर में यह जिम्मेदारी दी गई तो ऐसी अटकलें लगाई गईं कि आते ही वह केंद्र की मर्जी के अनुरूप ब्याज के बंधन खोलेंगे ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी हलचल आए। चुनावी साल में लोन सस्ता होना सत्तारूढ़ दल के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन रेपो रेट घटाने को सीधे-सीधे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला कहना गलत होगा। छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने आम राय से नीति को सत से न्यूट्रल बनाने का फैसला लिया। बहस सिर्फ रेपो रेट को स्थिर रखने और इसे घटाने के बीच थी और पलड़े का दूसरी तरफ झुकना लाजमी था। शतिकांत दास न सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लक्षणों का आकलन करके ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत का रुझान स्थिर रहने या नीचे जाने का है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से क्रूड की किल्लत पैदा होने की आशंका थी, जो अमेरिका की नरमी से खत्म हो गई।

अमेरिकी रिजर्व बैंक फेड ने अपनी दरें बढ़ाने को लेकर ठंडा रुख अपना लिया है, लिहाजा डॉलर भी तेजी से महंगा नहीं हो रहा। भारत समेत पूरी दुनिया में खाद्य वस्तुओं का सस्ता होना एक और राहत की बात है। चीन और दुनिया की कई और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सुस्त पडऩा एक अलग समस्या है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इस बीमारी से भी बची हुई है। राष्ट्रीय सांयिकी कार्यालय ने भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.2 फीसदी आंका है। रबी की बुवाई एक फरवरी तक पिछले साल से 4 प्रतिशत कम दर्ज की गई है लेकिन माना जा रहा है कि इस बार देर तक ठंड पडऩे से पैदावार अच्छी रहेगी। खुदरा और थोक वस्तुओं की महंगाई भी काबू में है। इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया तो ठीक ही किया।

आरबीआई ने किसानों को तोहफा देते हुए बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ा दी है। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बड़ी जमाराशि से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बहरहाल, रेपो रेट कम होने से बैंक होम लोन आदि की मासिक किस्त घटाएंगे या नहीं, कहना मुश्किल है क्योंकि फंसे हुए कर्जों का दबाव उन पर अब भी काफी है।

A new innovation era: India jumps eight places among 50 countries in global IP index

Patrick Kilbride, [The writer is senior vice president of the Global Innovation Policy Center at the US Chamber of Commerce.]

Source- TOI

If the new year is anything to go by, India is already signalling its position on innovation and creativity. The Supreme Court kick-started 2019 by upholding Monsanto's patent on genetically modified cottonseeds, suggesting that patent rights will not be hostage to political discretion. Additionally, the Indian government clarified that patented drugs will be protected from price controls for a period of five years, and also proposed definitive measures to criminalise film piracy.

This growing pro-innovation narrative is very welcome and not entirely surprising. Over time, the government has gradually invested in a series of incremental initiatives to improve the country's innovation ecosystem guided by the vision of the 2016 National Intellectual Property Rights (IPR) Policy.

Two days ago, the US Chamber of Commerce's Global Innovation Policy Centre released its seventh annual IP Index, 'Inspiring Tomorrow'. The Index analyses the IP climate in 50 countries, covering over 90% of global gross domestic product. It ranks economies based on 45 unique indicators that benchmark activity critical to building an innovation-led economy supported by robust patent, trademark, copyright, and trade secrets protection. It presents a data-driven view of global competitiveness based on the business community's investment criteria.

The 2019 IP Index showed that India ranked 36th of 50 economies – eight places up from 44th place last year – reflecting the importance that India's policymakers are placing on building an innovation ecosystem. For the second year in a row, India's score represents the largest gain of any country measured on the Index, re-emerging as the top global improver – but this time with a big leap.

The Index findings highlight the positive spillovers from India's broader economic reforms, captured by other global indices: The 2018 World Bank Doing Business Report ranked India as the "top global improver for a second consecutive year," and India registered "the largest gain of any country in the G20" on the 2018 WEF Global Competitiveness Report. The global economy benefits when the world's fastest growing major economy thrives.

The increase in India's score and rank can be attributed to reforms that better align India's IP environment with the international IP system, including its accession to the WIPO Internet Treaties, steps to initiate agreements to expedite patent examination with international patent offices, a dedicated set of IP incentives for small business, and administrative reforms to address the patent backlog.

India also performs well on some of the Index's new indicators. On two of these – tax incentives for creation of IP assets, and targeted IP incentives for small business – India scores full points. Targeted incentives for small business – including expedited review for patent filings, reduced filing fees, and technical assistance – make India a world leader with Brazil.

However, to maintain this momentum, much work remains to be done. Frugal innovation is a great starting point to build a culture of creativity and efficiency. But the leap from frugal to transformative innovation requires a system of property rights that enables significant, risky, long-term investments.

Indian policymakers will need to streamline the country's overall IP framework to better support transformative innovation and inspire creativity. For instance, innovators continue to be discouraged by superfluous patentability requirements, lengthy pre-grant opposition procedures, and lack of regulatory data protection. If a patent is granted, enforcement of its full term of 20 years remains a challenge – either through the looming possibility of price controls on patented products, or the threat of compulsory licenses. Online piracy is rampant, and the lack of enforcement capacity to seize counterfeit goods hurts business. A coherent trade secrets law is absent.

If India is to compete in the Fourth Industrial Revolution, it will need to look at today's IPR as the addition and subtraction of the knowledge economy. The industrial assets of tomorrow's economy are intangible: know-how, information, and data. Making a market for these assets will be far more complicated than simply protecting IP. An economy needs to walk before it can run, and all countries need to master IPR to prepare for tomorrow's intangible economy. India has its work cut out, and the 'josh' is high.